हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 88 लखनऊ, मंगलवार 11 नवंबर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

बेटी की शादी के लिए की जाएगी आर्थिक मदद, सरकार की योजना के तहत मिलेगा आवास

-योगी ने दिलाया जनता को विश्वास

एजेंसी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास दिलाने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के उपचार में आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं और पारदर्शिता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में एक वृद्ध महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। एक महिला ने बिटिया की शादी के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों को विवाह अनुदान योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया। एक अन्य महिला ने बिजली कनेक्शन में आ रही अड़चन की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए निर्देशित किया। जनता दर्शन में योगी ने कहा कि किसी को भी घबराने की

आवश्यकता नहीं है। सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैंए प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध् ा कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें चॉकलेट भी दिया।

टेकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट जेट के इंजन से निकलने लगा धुआ

'कोलकाता एयरपोर्ट पर मच गई अफरा-तफरी

एजेंसी

कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से ठीक पहले एक निजी जेट विमान के इंजन से धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद विमान को गहन निरीक्षण के लिए टैक्सी बे (विमानों को रखने का स्थान) में वापस ले जाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट ने तुरंत वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) को सूचित किया जिसने उसे रुकने और 'टैक्सी बे' में वापस आने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र (एनएससी) बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई अड्डा अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार छह यात्रियों को लेकर निजी जेट उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था तभी एक अन्य विमान के पायलट ने उसके इंजन से धुआं निकलता देखा।

वंदे मातरम का गायन मुसलमानों के लिए इस्लामिक ऐतबार से जायज नही : महमूद मदनी

एजेंसी

सहारनपुर। राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना को डेढ़ सौ वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रध ाानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वंदे मातरम गीत को पूरा का पूरा प्रस्तुत किया जाए और उसके जिन अंशों को पूर्व में हटाया गया था, उन्हें भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बातें देश के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों और उलेमाओं को बहुत अखर रही हैं। वह इस पर खुली आपत्ति भी जता रहे हैं। पूर्व में कई जनप्रतिनिधि मोहम्मद आजम खां, शफीकुर रहमान वर्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद संसद में भी इसके गायन को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। अब फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सांसद दारूल उलूम की मजलिस-ए-शूरा के सदस्य एवं जमीयत उलमाए हिंद के एक गुट के हाल ही में फिर से चुने गए अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यूनीवार्ता से बातचीत में मुसलमानों की आपत्ति के बारे में दो टूक कहा कि वंदे मातरम गीत में कुछ पंक्तियां ऐसी है। जिसमें मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में पेश कर उसकी पूजा वंदना के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मुसलमान ईश्वर एक है, इस विश्वास को मानने वाले हैं और उसी की इबादत करते हैं। इसलिए दूसरे की देवी देवताओं की इबादत करना उनके मजहबी विश्वास के खिलाफ है। मदनी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ऐसी हालत में मुस्लिमों को पूरे वंदे मातरम गीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय भी इस संबंध में अपना फैसला दे चुका है। मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि 26 अक्टूबर 1937 को गुरूदेव रविंद्र टैगोर ने पंड़ित जवाहर लाल नेहरू को लिखे पत्र में उनसे अनुरोध किया था कि वंदे मातरम गीत की पहली दो पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाए। उसके तीन दिन बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने टैगोर की सलाह को अपनी मान्यता दे दी थी तभी से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूरे गीत का ही गायन किया जाए।

भारत को दहलाने की नापाक साजिश का भंडाफोड़

फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स, 2 एके 47 व भारी गोला-बारूद बरामद

एजेंसी

श्रीनगर/फरीदाबाद। जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार हुए एक डॉक्टर के खुलासे के बाद पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक बरामद करने में सफलता हासिल की है। अधिकारियों ने जब्त पदार्थ को अब तक विस्फोटक आईईडी बनाने वाली सामग्री आरडीएक्स (आरडीएक्स) बताया है। पिछले सप्ताह, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद से दो कश्मीरी डॉक्टरों को गिरफ्तार करके एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक की पहचान आदिल अहमद राठेर के रूप में हुई है। वह दक्षिण कश्मीर के

काजीगुंड का निवासी है। पुलिस ने इससे पहले अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के एक डॉक्टर के लॉकर से एक राइफल बरामद की थी। पुलिस ने हालांकि फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बाहर एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर से पूछताछ के बाद लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गयी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस तीसरे डॉक्टर की भी तलाश कर रही है, जिसके इसी नेटवर्क का हिस्सा होने का शक है और जो फिलहाल फरार है। श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के समर्थन में लगे पोस्टरों की जांच के दौरान इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को एक डॉक्टर की पहचान करने में मदद मिली, जिससे पूछताछ के बाद मामले में शामिल एक अन्य चिकित्साकर्मी को गिरफ्तार किया गया। बरामद सामान में एक असॉल्ट राइफल मिली, जो दिखने में एके-47 जैसी है लेकिन आकार में उससे थोड़ी छोटी है। इसके साथ ही तीन मैगजीन, 84 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, आठ लाइव राउंड और दो खाली कारतूस भी बरामद किए गए। इसके अलावा बड़े और छोटे मिलाकर कुल बारह सूटकेस मिले, जिनमें विस्फोटकों और उपकरणों को छिपाया गया था। टीम को कई वॉकी-टॉकी सेट और अन्य संचार उपकरण भी मिले। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त अभियान लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और टीमें एक सक्रिय एंटी-टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थीं। उन्होंने पुष्टि की कि मुख्य आरोपी का नाम डॉ. मुजम्मिल है, जिसे 9-10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र गुप्ता ने कहा कि हथियार कहां से आए और कैसे यहां तक पहुंचाए गए, यह फिलहाल जांच का विषय है।

संक्षिप्त समाचार

एआई के दुरुपयोग से जज भी परेशान, सीजेआई गवई बोले-हमने भी देखीं अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरपयोग के बारे में जजों को भी मालूम है। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार कहा कि न्यायपालिका के लोगों को भी मॉर्फ्ड तस्वीरों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह की तकनीकों को नियंत्रित करने की पहल कार्यपालिका की ओर से होनी चाहिए, न्यापालिका से नहीं। दरअसल, आज समाज का बड़ा तबका किसी न किसी रूप से एआई के दुरुपयोग की वजह से परेशानी महसूस कर रहा है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है, हमने भी अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें देखी हैं।

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट तैयार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कानून मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की साजिश मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था. विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) द्वारा 23 फरवरी की घटना के संबंध में पारित आदेश को रद्द कर दिया।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जनगणना गुजरात की नई वेबसाइट का किया शुभारंभ

एजेंसी

गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में जनगणना गुजरात की नवीनतम वेबसाइट ेजजचेरूध्ध्हनरंतंज.बमदेने.हवअ.पदध् का शुभारंभ किया।गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के जनगणना निदेशालय द्वारा तैयार की गई यह वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को आधुनिक सुविधाओं, आसान मेनू और बहुभाषी सुविधाओं के साथ आसान पहुंच प्रदान करेगी।इस वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण की सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियोजन के माध्यम से संतुलित विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, वह जनगणना के माध्यम से जनकल्याण की टैगलाइन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट के शुभारंभ से इसे और बल मिलेगा। इस बार देश की आगामी जनगणना पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पहली बार स्व-गणना सुविधा भी शुरू की जा रही है, ताकि नागरिक अपना डेटा एक वेब पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमा कर सकें। इससे पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। राज्य जनगणना निदेशक सुजल मयात्रा ने इस वेबसाइट की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2027 की जनगणना के लिए पूर्वाभ्यास किया जा चुका है और विभिन्न मोबाइल ऐप्स का परीक्षण किया जा चुका है। इस जनगणना 2027 के पूर्व-परीक्षण

के लिए गुजरात के सूरत नगर निगम के 133 ब्लॉक, दाहोद के देवगढ़बरिया तालुका के 26 गांवों के 70 ब्लॉक और मोरबी के टंकारा तालुका के 25 गांवों के 60 ब्लॉक चुने गए हैं। जनगणना निदेशक ने इन चयनित क्षेत्रों में 10 से 30 नवंबर तक किए जाने वाले पूर्व-परीक्षण कार्य की भी जानकारी दी। इस वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य सचिव एमके. दास, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवंतिका सिंह और गुजरात के जनगणना निदेशालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वच्छ हवा बुनियादी अधिकार, नागरिकों को अपराधी की तरह क्यों देखती है सरकार : राहुल

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि स्वच्छ हवा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है लेकिन जब नागरिक साफ हवा के हक की मांग करते हैं तो सरकार उनके साथ अपराधी की तरह पेश आती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सोमवार को कहा कि संविधान ने हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है और उनके इस अधिकार की सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने लिखा स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दी गयी गारंटी का

हिस्सा है। जब नागरिक स्वच्छ हवा में जीने की अपनी बुनियादी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वायु प्रदूषण से करोड़ों भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों और देश के भविष्य को नुकसान पहुंच रहा है लेकिन वोट चोरी से सत्ता में आई सरकार इस गंभीर संकट को सुलझाने के बजाय चुप बैठी है और और इसका विरोध कर रहे नागरिकों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह जनता की आवाज दबाने के बजाय वायु प्रदूषण के संकट को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए और लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत सकारात्मक कार्रवाई करे।

कांग्रेस नेता रिजाल बोले-राष्ट्रपति की समझदारी से बच गया नेपाल, वर्ना मिट जाता देश का अस्तित्व और भारत का बढ़ जाता बोझ

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिनेंद्र रिजाल ने कहा है कि सितंबर में हुए ळमद-ៗ प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति के हस्तक्षेप ने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। उनके अनुसार, यदि राष्ट्रपति ने उस समय कदम नहीं उठाया होता, तो नेपाल अंतरराष्ट्रीय रूप से अलग-थलग" हो सकता था और हजारों लोग भारत-नेपाल की खुली सीमा पार कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाते। रिजाल ने कहा, "हम एक पराया देश बनने की कगार पर थे। अगर ऐसा होता, तो हमारे पड़ोसी (भारत) को भी हमारी समस्या का बोझ उठाना पड़ता। शुक्र है कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक और लंबे राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल किया और देश को एक बड़ी त्रासदी से बचाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का कदम न केवल संविधान की भावना के अनुरूप था बल्कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक भी था। "क्या यह सही था? हां, बिल्कुल। क्या यह संवैध ाानिक था? इस पर बहस हो सकती

है। लेकिन अगर राष्ट्रपति केवल संविध ाान की शब्दशः व्याख्या करते, न कि उसकी आत्मा को समझते, तो शायद हालात बेकाबू हो जाते। रिजाल ने माना कि सितंबर 8-9 के विरोध प्रदर्शनों में जनता का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भ्रष्टाचार, असमानता और प्रशासनिक उदासीनता से भी उपजा था। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनते चाहे वो सोशल मीडिया बैन के विरोध की हो या भ्रष्टाचार की तो हम एक बड़ी गलती करते। रिजाल ने प्रदर्शनकारियों को तीन वर्गों में बांटा-राजनीति से निराश युवाओं की भीड़, लूटपाट करने वाले अवसरवादी तत्व, घटनास्थल पर बाद में जाकर मलबे में कुछ खोजने वाले लोग। उन्होंने कहा,"अगर हमारे समाज में दो वर्ग रह गए हैं एक जिसके पास सब कुछ है और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं तो यह गुस्सा और असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। पूर्व मंत्री ने जोर दिया कि अब नेपाल को विश्वसनीय और निष्पक्ष चुनाव कराने पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

लैंड फॉर जॉब केस, बिहार में वोटिंग से पहले लालू परिवार को राहत, आरोप तय करने का आदेश 4 दिसंबर तक टला

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश चार दिसंबर तक के लिए टाल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर एजेंसी द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब इस मामले पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी, जब अदालत इस बारे में अपना निर्णय सुना सकती है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। सीबीआई ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव, उनकी

पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र के ग्रुप-डी श्रेणी में नियुक्तियां लालू यादव के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान की गईं, जिसके बदले में नियुक्तियों के लिए राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए। अदालत ने इससे पहले अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक डी. पी. सिंह ने किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां मानदंडों का उल्लंघन करके की गईं तथा लेन-देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और षड्यंत्र के समान है। आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है।

संपादकीय

कश्मीर घाटी में जो कुछ भारत के विरुध्द हो रहा, इसे जानने का अधिकार तो लोगों को है

भारत के अभिन्न हिस्सों में वर्षों से चली आ रही मारधाड़ की सच्चाई जानने का अधिकार तो जनता को होना चाहिए। वहां तो अनंत काल से अमावस्या ही अमावस्या है। 'कश्मीर घाटी' वर्षों से आग की लपटों में है, परन्तु देश के अन्य राज्यों में कश्मीर घाटी के प्रति मूकता का भाव क्यों? कश्मीर से कन्या कुमारी तक अपनी ही तो मातृभूमि है। फिर कश्मीर घाटी के लिए यह वितृष्णा क्यों? कश्मीर घाटी का मुसलमान तो 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलता चला आ रहा है? 'कश्मीर घाटी' में वर्षों से रिसते जख्मों पर कौन मरहम लगाएगा? क्यों वहां से कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया गया? क्यों 'कश्मीर घाटी' का हिंदू अपने ही घर में बेघर हो गया? भारत भूमि तो सभी धर्मों के लिए एक विस्तृत भूखंड है। 'कश्मीर घाटी' को क्यों इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है? 1947 के भारत विभाजन के बाद भी 'कश्मीर घाटी' क्यों स्वाभाविक रूप से हिंदोस्तान से न जुड़ सकी है? जिन्ना को हर हाल में पाकिस्तान बनाना था, बना लिया, फिर 'कश्मीर घाटी' में अराजकता क्यों? यह जानना तो भारतीय जनता का अधिकार है। बार–बार यही 'अरण्य रोदन' कि अब्दुल्ला परिवार कश्मीर घाटी की शांति का दुश्मन है। यदि अब्दुल्ला परिवार है तो उससे फैसलाकुन बात करो। आखिर पी.डी.पी. की मुफ्ती महबूबा को भी तो लाखों मतभेद होते हुए भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया ही था? महबूबा से तो अब्दुल्ला परिवार थोड़ा सॉफ्ट है। राजनीति में आज जो दुश्मन है, कल मित्र भी बन जाएगा। राजनीति कोई ठहरा तालाब नहीं बल्कि राजनीति तो एक बहता दरिया है। भारत के राजनेता विचार करें। कश्मीर तो भारत का एक अभिन्न अंग है। उसे सदा के लिए 'अनसुलझा मसला' नहीं रहने देना चाहिए। आज तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल को हम कश्मीर समस्या के लिए कोसते चले आ रहे हैं जबकि पंडित नेहरू को तो हमने 1964 में अलविदा कह दिया था। सन 1965, सन 1971 और सन 1999 तक हमने तीन युद्ध तो लड़ लिए। अब 'आप्रेशन सिंदूर' भी हमने कर लिया। 'कश्मीर घाटी' को स्थायी अमावस्या से बाहर नहीं निकाल सके। पंडित नेहरू के बाद तो केंद्र में बीसियों सरकारें भारत के लोगों ने बना लीं। इतने पर भी 'कश्मीर समस्या' तपती ही रही। पुलवामा और पहलगाम की जघन्य घटनाओं ने तो विश्व राजनीति को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान की पार्लियामैंट में मैंने स्पीकर से लेकर वहां के सभी सांसदों को सुना। सब के सब यही बोल रहे थे कि सारी घटनाएं भारत स्वयं करवा रहा है ताकि दुनिया आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और जब भी भारत की केंद्र सरकार को कोई झटका लगता है तो वह पाकिस्तान की ओर मुंह कर लेता है। पाकिस्तान कहता है कि वह खुद आतंकवाद से लड़ रहा है परन्तु यह सब कहने से पहले पाकिस्तान यह क्यों दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करता कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा आतंकवादी 'ओसामा बिन लादेन' पाकिस्तान के शहर अलावलपुर में अपना 'हैड आफिस' बनाए बैठा था? ऐसे में पाकिस्तान के राजनेताओं पर विश्वास कौन करेगा? 1980 से 2025 तक के कालखंड में 25,000 कीमती जानें आतंकवाद का शिकार हो चुकी हैं। राजनेताओं से लेकर सैन्य अधिकारियों और आम आदमी से लेकर पुलिस के जवानों तक, नौजवानों से लेकर बच्चों और बूढ़ों तक को इस आतंकवाद ने नहीं छोड़ा। 'कश्मीर घाटी' के अपने लोग ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें रास्ता बता रहे हैं। स्थानीय जनता ही आतंकवादियों के लिए 'रेकी' कर रही है। उन्हें खाने–पीने के लिए रसद पहुंचा रही है। कोई स्वयं विचार करे कि विभीषण के रहते क्या लंका बच सकती है? इन चीजों का उत्तर तो सरकार को ही देना है और 'कश्मीर घाटी' में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह जानना तो भारत के लोगों का अधिकार है। सरकार न जवाब दे परन्तु इस पर कोई 'सफेद यंत्र' या 'जांच आयोग' तो बिठा सकती है? अब तो सरकार ने धारा 370 भी हटा दी है। इसी धारा पर 1954 से विरोध होते रहे हैं न? अब सरकार उत्तर दे कि ड्क्षहदुओं के धार्मिक स्थान क्यों सुरक्षित नहीं? जम्मू में वैष्णो माता के मंदिर को लगातार खतरा जारी है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की अराध्य देवी 'खीर भवानी' का मंदिर हमेशा खतरे में रहा है। कश्मीरी पंडितों की दुकानों, मकानों, जायदादों, खेत–खलिहानों पर मुसलमान कब्जा जमाए बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती घाटी से निकाल दिया है। 'कश्मीर घाटी' में पाकिस्तानी झंडे लोगों ने अपने घरों पर लगा रखे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म क्यों? अतः यह जनता को जानने का अधिकार है कि कश्मीर घाटी में क्या हुआ, क्यों हुआ और नित्य बिना युद्ध के फौज के जवानों की लाशें तिरंगे में लिपटी उनके घर पहुंच रही हैं क्यों।

राशिफल

मेष :– समय के साथ समझौता करके चलने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझें और स्वयं को उसी ओर केंद्रित करें। पत्नी के साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

वृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकार लोगों से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली होगी।

कर्क :– भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का सही ढ़ंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन असंतुष्ट रहेगा। जरूरी कायरे में आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्य के प्रति भी ध्यान दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– परिवार की छोटी–छोटी बातों बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

तुला :– कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता हेतु नये उत्साह का संचार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होंगे।

वृश्चिक :– स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे।

धनु :– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्मित्ता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिले–जुले संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

मीन :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तिुष्ट पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर ही रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है।

सड़कों पर मौत की रफ़्तार पर ब्रेक कब लगेगा?

—डॉ प्रियंका सौरभ

भारत की सड़कों पर हर दिन लगभग चार सौ लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आँकड़ा किसी आपदा या महामारी से नहीं, बल्कि हमारी सड़कों पर व्याप्त अव्यवस्था और लापरवाही से जुड़ा है। अनेक योजनाएँ, अभियान और कानून बनने के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले देशों में गिना जाता है। सवाल यह नहीं कि सरकार ने कुछ किया या नहीं, बल्कि यह है कि हमने सड़क सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक असफलता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक संस्कृति की भी परीक्षा है। भारत में सड़क सुरक्षा पर चर्चा अक्सर किसी बड़ी दुर्घटना या प्रसिद्ध व्यक्ति के हादसे के बाद तेज होती है, लेकिन कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनती हैं, वे अधिकतर काग़ज़ों तक सीमित रह जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत विश्व की कुल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का लगभग ग्यारह प्रतिशत अकेले वहन करता है, जबकि हमारे पास विश्व की कुल गाड़ियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। यह असंतुलन किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र के लिए चेतावनी है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई गहरे और परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है कृ अवसंरचना की गुणवत्ता और डिजाइन में गंभीर खामियाँ। हमारे अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संकेतक, डिवाइडर, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा अवरोधक नहीं हैं। कई बार सड़कों का चौड़ीकरण बिना यातायात प्रवाह के वैज्ञानिक अध्ययन के किया जाता है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सड़कें वर्षा में टूट जाती हैं और वर्षों तक बिना मरम्मत के उपयोग में रहती हैं। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है कृ कमजोर प्रवर्तन प्रणाली। भारत में यातायात नियम तो हैं, पर उनके पालन की संस्कृति नहीं है। तेज रफ़्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के यात्रा करना और नशे की हालत में गाड़ी चलाना आम बात है। पुलिस बलों के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही तकनीकी प्रशिक्षण कि वे इन नियमों को सख़्ती से लागू करा सकें। "ई–चालान" जैसी पहलें केवल बड़े शहरों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यातायात नियंत्रण लगभग नाममात्र का है। तीसरा कारण है कृ ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था की खामियाँ। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कौशल का नहीं, बल्कि प्रक्रिया की औपचारिकता का प्रतीक बन गया है। प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण बिना समुचित परीक्षण के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप असुरक्षित चालक सड़कों पर उतर जाते हैं। कई देशों में वाहन चलाना एक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है, जबकि भारत में यह केवल एक अधिकार की तरह देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, वाहनों की तकनीकी सुरक्षा प्रणाली का अभाव भी दुर्घटनाओं में मृत्यु का बड़ा कारण है। अधिकांश वाहनों, विशेषकर ट्रक, बस और ऑटो श्रेणी में टक्कर–चेतावनी प्रणाली, एयरबैग, या ऊर्जा–अवशोषक ढाँचा नहीं होता। विकसित देशों में वाहन निर्माण के समय सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य हैं, परंतु भारत में ये केवल महंगे मॉडलों तक सीमित रहते हैं। वाहन उद्योग और नियामक संस्थाओं के बीच जवाबदेही का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्घटना के बाद की स्थिति और भी भयावह है। ट्रॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की कमी के कारण घायल व्यक्ति समय पर उपचार नहीं पा पाते। "स्वर्णिम घंटा" यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जीवन बचाने के लिए निर्णायक होता है, परंतु हमारे देश में यह घंटा अक्सर सड़कों पर तड़पते हुए बीत जाता है। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सेवाएँ भी सीमित हैं, और जो हैं, वे ईंधन या स्टाफ की कमी से प्रभावित रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक पक्ष भी गंभीर है। नीति आयोग के अनुसार, भारत हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग तीन प्रतिशत तक खो देता है। यानी न केवल लोग मर रहे हैं, बल्कि विकास की रफ़्तार भी घट रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी क्षति है। यह केवल आँकड़ों की बात नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के सम्मान का प्रश्न है। अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति को बदला कैसे जाए? सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा को प्रतिक्रियात्मक नहीं, निवारक नीति के रूप में अपनाना होगा। इसका अर्थ है कि दुर्घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो दुर्घटनाओं को रोके। इसके लिए सड़क निर्माण, वाहन प्रौद्योगिकी, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। पहला कदम होना चाहिए कृ वैज्ञानिक सड़क डिजाइन और रखरखाव। हर सड़क परियोजना में निर्माण से पहले "सड़क सुरक्षा लेखा–परीक्षण" अनिवार्य किया जाना चाहिए। सड़कें केवल चौड़ी नहीं, बल्कि सुरक्षित और समझदार हों। संकेतक, गति अवरोधक, क्रैश बैरियर और रात्रि प्रकाश जैसे तत्वों को डिजाइन का अभिन्न भाग बनाना होगा। उदाहरण के लिए, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में "शून्य मृत्यु गलियारा" (मतव थ्जंसपजल ब्वततपकवत) योजना के तहत मृत्यु दर में पचास प्रतिशत तक कमी आई है। दूसरा कदम, लाइसेंस व्यवस्था में सुधार। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह "लाइसेंस सेवा केंद्र" बनाकर पारदर्शी, डिजिटल और कौशल आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक चालक को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना अनिवार्य किया जाए। इससे भ्रष्टाचार घटेगा और योग्य चालक सड़कों पर उतरेंगे। तीसरा कदम, वाहनों में सुरक्षा प्रौद्योगिकी का प्रसार। सरकार को सभी वाहनों में एयरबैग, सेंसर और टक्कर चेतावनी प्रणाली जैसे फीचर अनिवार्य करने चाहिए। "भारत वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम" (भारत एनसीएपी) सही दिशा में है, परंतु इसे प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। चौथा कदम, पैदल यात्रियों और गैर–मोटर चालित वाहनों के लिए सुरक्षित अवसंरचना का विकास। हमारे शहरों में फुटपाथ अक्सर गायब हैं या दुकानों और पार्किंग में बदल जाते हैं। सुरक्षित ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर पुल और संकेत व्यवस्था से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। कोपेनहेगन और टोक्यो जैसे शहरों की तरह पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए समर्पित मार्ग विकसित करने होंगे। पाँचवाँ कदम, आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क को मज़बूत करना। हर पचास किलोमीटर पर ट्रॉमा केंद्र, चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा और हेल्पलाइन के साथ "राष्ट्रीय दुर्घटना प्रतिक्रिया जाल" तैयार किया जा सकता है। उपग्रह आधारित प्रणाली से एम्बुलेंस को शीघ्रतम मार्ग मिल सकता है। निजी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने का दायित्व कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, जनजागरूकता का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान, तथा मीडिया के माध्यम से निरंतर जनसंवाद से व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जब तक नागरिक स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई भी नीति स्थायी परिणाम नहीं दे पाएगी। कई देशों में सड़क सुरक्षा को राष्ट्र–निर्माण का अंग माना गया है। स्वीडन की "विजन ज़ीरो" नीति इसका उदाहरण है, जहाँ 1997 से यह लक्ष्य रखा गया कि किसी को भी सड़क पर मरना नहीं चाहिए। इस नीति ने डिज़ाइन, प्रवर्तन और तकनीक के संयोजन से मृत्यु दर को आधे से अधिक घटा दिया। भारत को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जहाँ मानव जीवन की कीमत सर्वोपरि हो। अंततः यह स्वीकार करना होगा कि भारत की सड़क सुरक्षा समस्या केवल अवसंरचना की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी है। जब तक लोग स्वयं अनुशासन को अपनाने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी कानून कारगर नहीं होगा। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। भारत आज आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर यह विडंबना है कि हर साल लाखों लोग केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमारी सड़कें असुरक्षित हैं। विकास का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति कृ चाहे वह चालक हो, साइकिल सवार या पैदल यात्री कृ स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। समय आ गया है कि सड़क सुरक्षा को "परिवहन मुद्दे" नहीं बल्कि "मानव अधिकार मुद्दे" के रूप में देखा जाए। यह केवल गति की नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का सवाल है। हमें तय करना होगा कि भारत की सड़कों पर रफ़्तार जीने का प्रतीक बने या मरने का कारण।

70 साल में भी वेस्ट यूपी नही बनी हाईकोर्ट बेंच

—अशोक मधुप

बिना सर्जरी के एक हफ्ते में बवासीर से छुटकारा पाने का असरदार तरीका! यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है टूटे, टेढ़े, ढीले दांत! पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग एक बहुत पुराना और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन है। लगभग 70 साल पुरानी यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन के कामयाब न होने की खास बात यह है कि आंदोलनरत वकील आदोलन से जनता को नही जोड़ सके। वह यह बताने में और जनता में मन में बैठाने में असफल रहे कि हाईकार्ट की बैंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनने से यहां के रहने वालों को क्या लाभ होगा? 1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ से दूरी अधिक है। साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की। वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा । जनता पार्टी के शासन में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग पर मुहर लगाई और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को कर उसे केंद्र सरकार

को भेजा। बनारसीदास सरकार एवं बाद में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में भी एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को संस्तुति प्रदान की गई। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 1970 और 1980 के दशक में, यह आंदोलन और भी जोर पकड़ने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया। इससे यह मांग राजनीतिक मुद्दा बन जरूर बन गई किंतु नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव में और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में कभी पूरी नही हुई। आज भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर नियमित रूप से आंदोलन करते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण मुवक्किलों और वकीलों को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और संसाधनों की कमी वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। इलाहाबाद में एक मुकदमे के लिए जाने का मतलब है, न केवल यात्रा का खर्च, बल्कि वहाँ रहने और खाने का भी खर्च। इसके अलावा, वकीलों की फीस भी अधिक होती है। यह सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय को बहुत महंगा बना देता है। एक बात और इलाहाबाद की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लखनऊ खंड पीठ से संबद्ध कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ किलोमीटर के आसपास कम हो जाती। लखनऊ पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है किंतु ऐसा भी नहीं किया गया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से आने वाले मामलों की बड़ी संख्या के कारण, न्याय में और अधिक देरी होती है। एक बेंच की स्थापना से मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर ष्भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी, और यह एक आत्मनिर्भर केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में भी यह आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से वकीलों के संगठन नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते हैं, वे धरने देते रहतें हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालांकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के सामने सबसे बडी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच की स्थापना से उनका काम और आय प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल देती है। एक मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की कमी ने इस आंदोलन को कमजोर किया है। अलग–अलग संगठन अपने–अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन पाती। हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर हो गए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग उठाने के बाद सांसद अब अधिवक्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराएंगे। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के लिए मिलने का समय मांगा है। सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं।मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नई पीठ ओर राज्य में चौथी हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधिघ्सूचना एक अगस्त को जैसे ही जारी हुई यूपी के मेरठ में सरगर्मियां बढ़ गईं। "पश्चघ्मि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति" ने तुरंत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चघ्मि यूपी के 22 जिलों के बार अध्यक्षों और महामंत्री के साथ बैठक की. समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच खुल सकती है तो यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट की तीसरी बेंच क्यों नहीं स्थापित हो सकती? मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल कर प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना का आंदोलन पिछले लगभग 70 साल से जारी है। कब तक जारी रहेगा, यह भी नही कहा जा सकता।इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 70 साल चलने वाला यह आंदोलन लंबी अवधि तक चलने वाले आंदोलनों में जरूर दर्ज हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आवारा कुत्तों की समस्या!

—विनीत नारायण

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या एक जटिल सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा रही है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, स्कूलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और उन्हें नसबंदी, टीकाकरण के बाद निश्चित आश्रमों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि इन कुत्तों को उनकी मूल जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा ताकि इन सार्वजनिक स्थलों से उनकी उपस्थिति खत्म हो सके। यह फैसला भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी बढ़ती समस्या जैसे कि कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय 2 सप्ताह के अंदर सभी सरकारी और निजी स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड आदि की पहचान करें जहां आवारा कुत्ते उपस्थित हैं। इसके बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रमों में स्थानांतरित करें,जहां उन्हें न सिर्फ नसबंदी और टीकाकरण दिया जाएगा बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्रवाई में बाध्‌ा डालता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 13 जनवरी 2026 को समीक्षा के लिए पुनरू लाया जाएगा। जानवर प्रेमियों और पशु अधिकार संगठनों ने इस आदेश पर व्यापक असंतोष जताया है। उनका कहना है कि इस तरह के आदेश से कुत्तों के प्रति चिंता और संरक्षण कम हो सकता है। कई संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही जारी रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इलाके में कुत्तों की आबादी नियंत्रित रहती है और कुत्तों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे पशु कल्याण बोर्ड के पुराने सुझावों का हवाला देते हैं, जिनमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों का पुनरू उनके क्षेत्र में छोडना बेहतर तरीका है न कि उन्हें जोर जबरदस्ती आश्रमों में बंद करना। कई जानवर प्रेमी और समाजसेवी समूह आशंकित हैं कि इस कदम से आवारा कुत्तों की संख्या और व्यवहार संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पशु प्रेमी जो जानवरों के कल्याण के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए। यह आदेश केवल कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने की बात नहीं करता बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित और मानवीय वातावरण प्रदान करने पर भी जोर देता है। नसबंदी और टीकाकरण जैसे कदम न केवल कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करेंगे बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। सड़कों पर रहने वाले कुत्ते अक्सर भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझते हैं, जिसके कारण वे आक्रामक हो सकते हैं। आश्रय स्थलों में उन्हें नियमित भोजन, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित स्थान मिलेगा जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यदि इसे सही ढंग से अमल में लाया जाए तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। केवल दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को देखते हुए, इसे अमल में लाना एक चुनौती हो सकती है। सरकार को बड़े पैमाने पर आधुनिक आश्रय स्थल बनाने होंगे जो स्वच्छता, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हों। इन आश्रय स्थलों में पशु चिकित्सकों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। पशु प्रेमियों की मानें तो इस आदेश को जारी करते समय कुछ सावधानियों और वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना आवश्यक था जैसे, स्थानीय आश्रमों की संख्या, संसाधन और देखभाल क्षमता का आकलन, कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए आम लोगों में जागरूकता और सामाजिक समन्वय, नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को उनके इलाके में छोडने की नीति, कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा, पशु अधिकार समूहों, नगर निगम और प्रशासन के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत अधिक है और प्रबंधन के लिए अलग–अलग राज्यों में नियम चलाए जाते हैं, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और पुनरू छोडना शामिल है। उदाहरण स्वरूप, जयपुर और गोवा जैसे शहरों ने इस विधि से कुत्तों से होने वाली बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। दूसरी ओर, विश्व के कई देशों ने भी अपनी–अपनी रणनीतियां अपनाई हैं।

भारत में अब पैदा नही होना चाहिए कोई नया जिन्ना-योगी

सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम, गोरखपुर में सरदार पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को दिखाई हरी झंडी

संवाददाता

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत में अब फिर कोई जिन्ना पैदा ना हो सके। यदि कोई जिन्ना पैदा हो जाता है तो उसे दफन करना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि देश में दोबारा विभाजन की स्थिति न उत्पन्न हो।उन्होंने कहा है कि आज हमें भाषा एवं जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है।उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य होगा। जिस वंदे मातरम गीत ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थीं, उसी का विरोध जिन्ना ने किया था। यदि कांग्रेस ने जिन्ना का विरोध किया होता तो देश का बंटवारा न होता। अब भारत में दूसरे जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। यदि जिन्ना पैदा हुआ तो उसे दफन कर देंगे। सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन किया और कहा कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा उन्हीं की है। सरदार पटेल देश की सभी रियासतों को एक किया लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। बीते 9 नवंबर को ही बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैलियों को संबोधित करके वापस आए। अब गोरखपुर से उन्होंने बिहार को भी सन्देश भेजा है कि भाषा और जातियों के नाम पर बांटने की साजिश की जा रही है, लेकिन हमें बंटना नहीं है। उन्होंने जिन्ना की विभाजनकारी सोच का जिक्र कर यह राष्ट्रीय एकता का भी मैसेज बिहार के मतदाताओं को भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता पदयात्रा की शुरुआत की थी। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में पदयात्रा भारतीय

जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। गोरखपुर में यूनिटी मार्च एकता पदयात्रा की अगुआई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की।

योगी सरकार में शामिल मंत्री ने कहा बिहार में सत्ता से बाहर होगा एनडीए!

मनोज श्रीवास्तव

लखनऊ। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के पूर्व उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी और एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगा। राजभर ने दावा किया कि जनता बिहार में अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को समर्थन दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद है। बिहार में जब महिलाएं ज्यादा वोटिंग करती हैं तब राजद की सरकार बनती है। एनडीए गठबंधन की तरफ से एक भी सीट न मिलने से नाराज सुभासपा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है।सुभासपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 64 प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आये राजभर ने पत्रकारों से बात–चीत किया। उन्होंने कहा कि वह दस दिन बिहार में रहे और महिलाओं से बात करने पर पता किया तो वह बोली कि राज्य सरकार हमारा उनका ही पैसा हमें उन्हें वापस दे रही है, कोई अहसान नहीं कर रही है। राजभर ने कहा कि चुनाव में चर्चा में आने के लिए कई नेता अपने पर गोबर फेंकवाते हैं। एक नेता को मैं जानता हूं कि जिन्होंने चुनाव जीतने को के लिए पुलिस से कह कर अपने ऊपर लाठी चलवाई और चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव के बार में उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की बी टीम हैं। मध्य प्रदेश में बोले कि कांग्रेस को वोट न दो जबकि कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। यही महाराष्ट्र और दिल्ली में किया। बिहार में चाहे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने काम नहीं किया। राजभर ने कहा कि बिहार में गरीब और अमीर के बीच लंबी खाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में यदि उनके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो वह एनडीए को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत पेंच है हैं। उन्होंने बताया कि इसके पीछ कि एक वजह ये भी है कि वहां (बिहार) ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ हैं। प्रशांत किशोर भी सबके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कोई आश्वस्त नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, जनता का जो मिजाज है वो समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में नेता चाहे जितना बोल ले। राजभर ने कहा कि नेता लोगों का बस चले तो एक दिन में पूरी सरकार गिरा दें, लेकिन जनता ही मालिक है।

संक्षिप्त

किराना के गोदाम में लगी आग, 80 लाख का नुकसान

संवाददाता

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक किराना की थोक दुकान और गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर 4 फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में ऊपर रह रहे परिवार ने पड़ोस की छत के रास्ते नीचे उतर कर जान बचाई। बंथरा कस्बे में कानपुर रोड किनारे पुरुषोत्तम गुप्ता और संतोष गुप्ता का तीन मंजिला मकान है। इसके बेसमेंट और भूतल पर उनकी मंगलम ट्रेडर्स नाम से किराना की थोक दुकान और गोदाम है। ऊपरी मंजिल पर दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार

शाम को परिवार एक समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब 12 बजे घर लौटकर सो गया। देर रात लगभग पौने दो बजे अचानक बिजली गुल हो गई। संतोष गुप्ता ने बाहर निकलकर देखा, तो बेसमेंट से तेज धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने शोर मचाया। परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और बगल के मकान की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला।

जनता दर्शन बना जन संवाद का सशक्त माध्यम : केशव मौर्य

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित व प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन व युवा उपस्थित रहे। लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पुलिस कार्यवाही, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी अपनी समस्याएं रखीं। जिस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी जनसमस्या के समाधान में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जरूरतमंदों व पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और किसी भी पीड़ित को निराश नहीं लौटना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हर व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है। समस्याओं का त्वरित व संतोषजनक समाधान अधिकारियों की जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि विवाद व अवैध कब्जों के मामलों को संवेदनशीलता और गंभीरता से निपटाया जाए, और जहां आवश्यक हो, वहां कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में करीब तीन दर्जन से अधिक जिलों से लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने इटावा, फतेहपुर, बलिया, शाहजहांपुर, कासगंज, औरैया, बांदा, जालौन व लखीमपुर के अधिकारियों से सीधे दूरभाष पर बात कर मौके पर निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा और किसी को भी बार–बार भटकना नहीं पड़ेगा।

महिला ने फांसी लगाई, घर से 500 मीटर दूर आम के पेड़ पर लटकता मिला शव

संवाददाता

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान अन्दपुर देव निवासी ज्ञानमती (65) के रूप में हुई है। उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। ज्ञानमती अपने बेटे रामबाबू के साथ रहती थीं, जबकि उनके दो अन्य बेटे दीपक और गनेश प्रसाद अलग रहते हैं। सोमवार सुबह करीब 10 बजे ज्ञानमती बिना कुछ बताए घर से चली गईं। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटीं, तो उनके बेटे रामबाबू ने उन्हें खोजना शुरू किया। खोजते हुए रामबाबू गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां का शव आम की पेड़ से लटकता देखा। धोती से फंदा लगा था। रामबाबू के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। सभी की मदद से ज्ञानमती को

पेड़ से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

सफल नहीं बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्तिबनने का प्रयास करें छात...

आईआईएसई परिसर में प्रो. अभिषेक मिश्रा का प्रेरणादायक संबोधन

संवाददाता

लखनऊ। कल्याणपुर के कंचना बिहारी मार्ग पर स्थित आईआईएसई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सोमवार को प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर, अतिथि वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अपने उद्बोधन में प्रो. मिश्रा ने सफलता, नेतृत्व, और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय पर विद्यार्थियों से प्रेरणादायक संवाद किया। उन्होंने कहा कि "जीवन में सफलता से अधिक महत्त्वपूर्ण है महत्व प्राप्त करना ,क्योंकि सफलता केवल स्वयं के लिए होती है, जबकि महत्व दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से मिलता है।"उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे केवल सफल नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी से ही प्राप्त की जा सकती है।" कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रो. मिश्रा से कई प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए युवाओं को गहराई से सोचने और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखने की सलाह दी। इस अवसर पर आईआईएसई ग्रुप के सीएमडी फिरदौस सिद्दीकी, सीएफओ बी. डी. सक्सेना, प्रिंसिपल डॉ. शैल मिश्रा, तथा डायरेक्टर डॉ. अरुण शुक्ला की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही संस्थान के सभी संकाय सदस्य, कर्मचारी एवं कॉलेज के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन डायरेक्टर डॉ. अरुण शुक्ला द्वारा दिए गए वोट ऑफ थैंक्स के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने प्रो. अभिषेक मिश्रा को उनके प्रेरक संबोधन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

समाज के बजाय अपना कल्याण, अब फंसे

–योगी एक्शन, चार अधिकारी बर्खास्त

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। चाहे मामला कितना भी पुराना हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लाभार्थियों तक पहुंचने वाली हर राशि की जवाबदेही तो तय होनी ही है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की निगरानी में जांच के बाद चार अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, तीन रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन में स्थाई कटौती के साथ सरकारी नुकसान की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कार्यवाही श्रावस्ती, मथुरा, शाहजहांपुर, हापुड़ और औरैया जिलों में डेढ़ दशक से भी पुराने स्कॉलरशिप, फीस रिफंड, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और पेंशन वितरण से जुड़े घोटालों पर आधारित हैं। श्रावस्ती की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक तैनात रहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के साथ स्कॉलरशिप और फीस रिफंड की राशि में बड़े पैमाने पर गबन करने का उन पर आरोप है।मीना श्रीवास्तव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी पर स्कॉलरशिप और फीस रिफंड में घपले का आरोप लगा है. उन्हें बर्खास्त करने के साथ 19.25 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश हुए हैं। हापुड़ के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार व्यास पर छात्रों की बजाय सीधे शिक्षण संस्थानों के खातों में राशि भेजने और छात्रों की डिटेल में छेड़छाड़ करने का आरोप है। व्यास को बर्खास्त कर 3. 23 करोड़ रुपए की वसूली का निर्देश जारी हुआ है। शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार पर स्कॉलरशिप और फीस रिफंड में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है।उन्हें बर्खास्त कर 2.52 करोड़ रुपए की वसूली तय की गई है।रिटायर्ड अधिकारियों में औरैया के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री भगवान शामिल हैं। उन पर 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर पेंशन की राशि अन्य खातों में डालने का आरोप है। 34 लाख रुपए के गबन में से 20 लाख रुपए की वसूली उनके खिलाफ की जाएगी और उनकी पेंशन में 10 प्रतिशत की स्थाई कटौती होगी। मथुरा के ही रिटायर्ड अधिकारी विनोद शंकर तिवारी के खिलाफ भी 1.96 करोड़ रुपए के सरकारी नुकसान का मामला दर्ज हुआ है। उनकी पेंशन में 50 प्रतिशत की स्थाई कटौती के साथ वसूली के आदेश दिए गए हैं।इसी जिले के एक अन्य रिटायर्ड अधिकारी उमाशंकर शर्मा पर मान्यता विहीन संस्थाओं को 2.53 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रिलीज करने और आईटीआई के 5526 छात्रों को गलत तरीके से लाभ देने का आरोप है। 88 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई उनके खिलाफ होगी और पेंशन में 50 प्रतिशत की स्थाई कटौती लागू की जाएगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की नोकझोंक, NSUI ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। एनएसयूआई सदस्यों ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद विश्वविद्यालय कैंपस में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन में जमकर नोकझोंक हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मार्च रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया गया है। वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह वोट चोरी हो रही है, उसके प्रमाण दिए। यह स्पष्ट है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीती है, सत्ता में आई है।

इसी संदेश को हम प्रत्येक छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई का अभियान आज लखनऊ विश्वविद्यालय समेत पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में चल रहा है। बिहार में एनडीए हारने जा रही है। 14 नवंबर को नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जिसका डर सबको सता रहा है। प्रदर्शन में शामिल अहमद ने कहा कि इस देश के अमीर गरीब सब में एक चीज सामान्य है, वह वोट की ताकत। यह सरकार उस ताकत को भी छीनना चाह रही है। यह भी ताकत हमसे ले लिया गया तो इस देश में समानता खत्म हो जाएगा। शुभम ने कहा कि बीजेपी का नाम बदल गया है वह ब्राजील जनता पार्टी हो गया है। राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग का खुलासा किया, मगर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन किसी तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। गरीबी , बेरोजगारी , भुखमरी जैसे मुद्दों से भटकाकर आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र राणा सुधांशु शर्मा ने कहा कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा है अभियान को खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। हरियाणा में ब्राजील की मॉडल वोट कर रही है जिसका साक्ष्य राहुल गांधी ने दिया। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके सत्ता में आने वालों को हम लोग बाहर फेंकेंगे। प्रत्येक घर तक जाकर हम बताएंगे कि कैसे उनके अधिकारों की हत्या हो रही है। अंतिम सांस तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे।

कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के सहयोग से लुलु मॉल में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। लुलु मॉल, लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारत में हर आठ मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवाती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रोकथाम योग्य और समाप्त किया जा सकने वाला कैंसर घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य है कि 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को समाप्त किया जाए, जिसके लिए आवश्यक है। 9 से 26 वर्ष की लड़कियों का टीकाकरण 30 से 60 वर्ष की महिलाओं की स्क्रीनिंग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान इस उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है और मानता है कि जागरूकता, प्रारंभिक जांच और टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के प्रमुख उपाय हैं। कार्यक्रम को रोचक और सहभागिता–आधारित बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिता, गेम्स और गिफ्ट वितरण जैसे कई आकर्षक आयोजन किए गए। इस अवसर पर प्रो. एम. एल. भट्ट, निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान, डॉ. सबुही कुरैशी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी विभाग, प्रो. विजेन्द्र कुमार, डॉ. वरुण विजय, तथा डॉ. सौम्या गुप्ता सहित संस्थान के अन्य वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। इन सभी विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों से संवाद किया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और नियमित स्क्रीनिंग तथा टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। लुलु मॉल के रीजनल मैनेजर समीर वर्मा ने कहा, "लुलु मॉल सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी गतिविधियों का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि लुलु केवल एक शॉपिंग और रिटेल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि समाज के प्रति योगदान देने वाला एक मंच भी है। यह जागरूकता कार्यक्रम हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।" यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और उपस्थित लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि कृ "जागरूकता, जांच और टीकाकरण के माध्यम से हम मिलकर सर्वाइकल कैंसर को समाप्त कर सकते हैं।

भाजपा ने लोकतंत्र को समझ लिया है अपनी संपत्ति–अखिलेश

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को अपनी संपत्ति समझ लिया है। प्रशासन से लेकर आयोग तक सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ही बेईमानी और छल का खेल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान की शुरुआत मतदाता सूची की अनियमितताओं से की। उन्होंने कहा कि कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता सूची से समाजवादी पार्टी समर्थकों के नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह से शिकायतें आ रही हैं, पता नहीं और कितनी जगहों से आएंगी। अखिलेश ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि वह इस पर स्वतः संज्ञान ले और मतदाता सूची की पुनः जांच कराए।पूर्व मुख्यमंत्री ने यूपी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी भाजपा के इशारे पर चल रही है।

बिरसा मुण्डा को जनजाति समुदाय देता है भगवान की तरह सम्मान-जयवीर

संवाददाता / लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण ने लोकभवन में लोकनायक बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के अंतर्गत होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। जयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हमारी जनजाति समुदाय का अतुलनीय योगदान है। बिरसा मुण्डा को जनजाति समुदाय भगवान की तरह सम्मान देता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 लोकनायक बिरसा मुण्डा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि जनजाति गौरव दिवस से अवसर पर 13 से 18 नवम्बर तक राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर के परिसर में किया जा रहा है। 15 नवंबर को सोनभद्र में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़े रहेंगे। यह उत्सव "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को जनजातीय संस्कृति के माध्यम से सशक्त बनाने का एक सशक्त प्रयास है। इस आयोजन में प्रदेश और देश के विभिन्न अंचलों की जनजातियों की भाषाई, सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक विविधताओं का संगम देखने को मिलेगा। जनजातीय भाषाओं की मधुरता, लोकगीतों की आत्मीयता, और पारंपरिक वेशभूषा की रंगीनता इस उत्सव को अनूठी पहचान प्रदान करेगी।

उत्तराखंड में बढ़ा चिकित्सा शिक्षा का दायरा

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में दूर हुई फैकल्टी की कमी, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर व देहरादून को मिली कैथ लैब

बीएनई

देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ–साथ मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही नये मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एमबीबीएस व पीजी की सीटों में वृद्धि कर छात्र–छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई के अवसर प्रदान किये। इन संस्थानों में शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिये समय–समय पर योग्य और अनुभवी संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर फैकल्टी की कमी को दूर करने का प्रयास किया, साथ ही मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूर हुई फैकल्टी की कमी राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को दुरूस्त करने के बड़े स्तर पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति है। वर्ष 2025 में संकाय सदस्यों की कमी को पूर्ण करने के लिये 439 असिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान हैं। इसके साथ ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर संकाय सदस्यों की भी नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 26 नर्सिंग टयूटरों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एक प्रोफेसर व 6 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति भी कर दी गई है। जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1248 नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जिससे सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई है। हरिद्वार में शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में स्थापित मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो कि राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 100 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया। जबकि शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। कैथ लैब की मिली सुविधा राज्य सरकार के प्रयासों से अब श्रीनगर व देहरादून में मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक कैथ लैब की सुविधा आम लोगों की सुलभ की जा रही है। जिससे हृदय संबंधी बीमारियों के उन्नत उपचार की जा रहा है। इससे न केवल प्रदेश के मरीजों का लाभ पहुंच रहा है बल्कि मेडिकल के विद्यार्थियों को भी नई तकनीक के व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। शीघ्र ही कैथ लैब की सुविधा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू कर दी जायेगी। आई बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्रीनगर में नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत 'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र' की स्थापना कर दी गई है। जहां पर आम लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधाएं दी जा

रही है। भौतिक संसाधनों में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों को साधन सम्पन्न बनाया जा रहा है। दून चिकित्सालय में 500 बेड का अस्पताल व राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर में 320 बेडेड यूजी हॉस्टल, 20 बेडेड इंटर्न हॉस्टल, 56 बेडेड एसआर हॉस्टल तथा टाईप–5 के 72 आवासीय भवन बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य भी गतिमान है। बयान राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल एजुकेशन और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए नए चिकित्सा एवं नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के साथ–साथ मौजूदा संस्थानों में अत्याधुनिक संसाधन, उपकरण और योग्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

एनसीएल में 16वीं अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

बीएनई

सिंगरौली। एनसीएल के ककरी क्षेत्र के एकलव्य मैदान में आज जोश और उत्साह से लबरेज़ माहौल में 16वीं अंतर–क्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। एनसीएल के सभी क्षेत्रों और इकाइयों से टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में 370 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 130 महिला प्रतिभागी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि निदेशक (तकनीकी/संचालन), एनसीएल सुनील प्रसाद सिंह ने सुरक्षा ध्वज फहराकर की। तत्पश्चात उन्होंने परेड की सलामी ली और सभी प्रतिभागी टीमों से परिचय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिला कर्मियों के साथ–साथ एनसीएल परिवार की होम मेकर्स (गृहणियों) की भागीदारी, घर से लेकर कार्यस्थल तक प्राथमिक उपचार और सुरक्षा की संस्कृति में नारी शक्ति की सशक्त भूमिका को रेखांकित कर रही है। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी/संचालन) सुनील प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में जोश और उत्साह के साथ प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता को सफल बनाने का आह्वान किया। चिकित्सा सेवा में फर्स्ट एडर की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार की जानकारी और सजगता, सुरक्षित कार्यस्थल की अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल अच्छे प्राथमिक उपचारकर्ता तैयार करते हैं बल्कि ज्ञान और अनुभव भी बढ़ाते हैं। उन्होंने एनसीएल के चिकित्सा एवं सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मियों और संविदा कर्मियों को इस आयोजन में योगदान हेतु सराहा। एनसीएल की लगभग 6000 घरेलू गृहणियों को प्राथमिक उपचारकर्ता बनने हेतु दिए गए प्रशिक्षण को नवाचारी पहल बताते हुए उन्होंने इसे एनसीएल की सामाजिक जिम्मेदारी और सशक्त नारी शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) पी. डी. राठी, सीएमएस (एनसीएल) विवेक खरे, सीएमएस (एनएससी) पंकज कुमार, महाप्रबंधक ककरी क्षेत्र प्रदीप कुमार जाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं ने प्रदर्शनियाँ भी लगाईं हैं ।

11 नवंबर को अहमदाबाद में होगा 'इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम

टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश के अवसरों की होगी प्रस्तुति

बीएनई

रायपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 11 नवंबर को अहमदाबाद में "इन्वेस्टर कनेक्ट" कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य गुजरात के उद्योग जगत के साथ औद्योगिक साझेदारी को मज़बूत करना और दोनों राज्यों के बीच निवेश व व्यापारिक अवसरों का विस्तार करना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के बढ़ते औद्योगिक इकोसिस्टम, प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेश–अनुकूल प्रशासनिक ढांचे को प्रदर्शित करेगा। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर विभिन्न सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषताओं पर प्रस्तुति देंगे। इस पहल के ज़रिए उद्योग स्थापित करना और संचालित करना पहले से अधिक सरल, तेज़ और लाभदायक बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता निवेशकों और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच वन–ऑन–वन बिज़नेस मीटिंग्स रहेंगी। इन चर्चाओं का फोकस टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा – जहाँ छत्तीसगढ़ ने नवाचार और प्रोत्साहनों से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की है। राज्य सरकार इस अवसर पर प्रमुख निवेशकों को "इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर" भी प्रदान करेगी, जिससे परियोजना स्वीकृति और औद्योगिक सहयोग की प्रक्रियाओं को त्वरित और सुगम बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के सफल आयोजन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बस्तर और रायपुर में हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ दस महीनों में 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की तेज़, स्थिर और निवेशक–केंद्रित शासन प्रणाली पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। नवाचार, स्थायित्व और इज ऑफ डूइंग बिज़नेस पर फोकस के साथ छत्तीसगढ़ आज भारत के हृदयस्थल में एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन गया है। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश की असीम संभावनाएँ हैं। पारदर्शी प्रणालियाँ, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों के लिए सहयोगी माहौल छत्तीसगढ़ को लंबे समय के लिए एक विश्वसनीय और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं।

खेल मंत्रालय ने 25 खेलों में 320 सहायक कोच की नियुक्ति को दी मंजूरी

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए अपनी पदक रणनीति के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्रों में 25 खेलों के लिए 320 सहायक कोचों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि जल क्रीड़ा, साइकिलिंग और टेनिस जैसे खेल सहित उन खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं लेकिन उनमें पदक जीतने की अपार संभावनाएं हैं। मांडविया ने कहा, ''इसमें साई केंद्रों के प्रमुख खेलों को शामिल किया जाएगा। चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित और पारदर्शी होगी और इसमें केवल वे ही शामिल होंगे जो अपने–अपने क्षेत्र में अव्वल या लाइसेंस धारक हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम खेलों को महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे देश में समग्र खेल संस्कृति में सुधार होगा। टेनिस, कयाकिंग और कैनोइंग जैसे खेल कभी–कभी उतना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें अपार संभावनाएं हैं।''मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के वादे के अनुसार, ''सुरक्षित खेल वातावरण'' के निर्माण और ''लैंगिक गुणवत्ता'' को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत भर्तियां महिलाओं की होंगी। उन्होंने कहा, ''जहां तक खेल विकास का सवाल है तो सहायक कोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की प्रतिभाओं को निखारते हैं। यह भर्ती अभियान का पहला चरण है और इस पहल के पूरा होने के बाद दूसरे चरण में 320 और कोच की भर्ती की जाएगी।

हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 267 अंक चढ़ा, निफ्टी 25500 के ऊपर

एजेंसी

नई दिल्ली। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और ब्लू–चिप शेयरों में खरीदारी के चलते पिछले तीन सत्रों की गिरावट के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। इसके अलावा, कारोबारियों ने कहा कि ताजा विदेशी पूंजी प्रवाह से भी निवेशकों की धारणा को समर्थन मिला। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 267.74 अंक या 0.32 प्रतिशत चढ़कर 83,484.02 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 84.90 अंक या 0.33 प्रतिशत बढ़कर 25,577.20 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों का हाल सेंसेक्स की 30 कंपनियों में एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और भारती एयरटेल के शेयरों में लाभ रहा। वहीं ट्रेंट लिमिटेड, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे।

मलिंगा–बोल्ट या राशिद नहीं, हाशिम अमला ने इस भारतीय को बताया IPL का सबसे मुश्किल गेंदबाज

एजेंसी

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतरराष्ट्रीय करियर में कई रिकॉर्ड्तोड़े और बनाए। उनकी क्लासिक बैटिंग स्टाइल हर किसी का मन मोह लेती थी। हालांकि, उन्हें आईपीएल में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि, अमला ने अब एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में उन्हें किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगा। अमला ने भारत के जसप्रीत बुमराह को सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया और कहा कि उन्हें सिर्फ बुमराह का सामना करना सबसे मुश्किल लगा। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अमला ने बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें दुनिया के सबसे स्किलफुल ऑल–फॉर्मेट गेंदबाज बताया। बुमराह को गेंदबाजी करते देखना ही सुंदर अनुभव है अमला ने कहा, शबिलकुल बुमराह। वह शानदार गेंदबाज हैं और आप देख सकते हैं कि भारत के लिए उन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी की है। मेरे लिए वह सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी थे। बुमराह न सिर्फ तेज गेंदबाजी करते हैं बल्कि उनकी विविधता और नियंत्रण अदभुत है। उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है।श बुमराह को अमला ने तकनीकी दृष्टि से सबसे कठिन गेंदबाज बताया, जो किसी भी बल्लेबाज को असमंजस में डाल सकते हैं। श्प्स् में अमला का शानदार रिकॉर्ड हाशिम अमला ने आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए 2016 और 2017 सीजन खेले। उन्होंने कुल 16 पारियों में 577 रन बनाए और उनका औसत 44.28 का रहा। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141.76 का रहा। अमला ने आईपीएल में दो शतक भी लगाए थे और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से भारतीय दर्शकों का दिल जीता था। अगर दोबारा मौका मिले, तो किस टीम के लिए खेलेंगे? पॉडकास्ट के दौरान जब अमला से पूछा गया कि अगर उन्हें दोबारा आईपीएल खेलने का मौका मिले तो किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे?

अमेरिका को गैलियम-जर्मेनियम जैसे अहम तत्वों पर मिली राहत, चीन ने हटाए निर्यात प्रतिबंध

एजेंसी

बीजिंग। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे तत्वों पर अमेरिका के लिए लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि यह फैसला कुछ दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर लागू नियंत्रण उपायों के आंशिक निलंबन से जुड़ा है। इसमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे औद्योगिक पदार्थ शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह निलंबन श्घोषणा संख्या– 46 (2024) की दूसरी धारा पर लागू होगा और यह नौ नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पहले इस धारा के तहत अमेरिका को इन औद्योगिकी पदार्थों के निर्यात पर रोक थी और ग्रेफाइट के निर्यात पर सख्त जांच की शर्तें थीं। वहीं, पहली धारा पहले की तरह लागू रहेगी, जिसमें अमेरिकी सेना या

सैन्य उपयोग के लिए दोहर उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर रोक है। वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी निलंबन केवल दूसरी धारा के लाइसेंस और समीक्षा से जुड़ी पाबंदियों पर लागू होगा। पिछले साल दिसंबर में चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति चीन में बने दोहरे उपयोग वाले सामानों को अमेरिकी संस्थाओं को अवैध रूप से भेजेगा, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच एक अहम व्यापार और आर्थिक समझौता हुआ। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात के बाद हुआ। इस समझौते में चीन ने दुर्लभ खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के निर्यात पर लगे निर्यात प्रतिबंधों को निलंबित करने, अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ हटाने और अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार और लकड़ी की बड़ी मात्रा में खरीद फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। इसके अलावा, चीन अब नेक्सपेरिया की अपने देश में स्थित इकाइयों से व्यापार दोबारा शुरू करने की अनुमति देगा और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों की जांच खत्म करेगा। इसके बदले में अमेरिका ने भी कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई है। वह फेंटानिल नियंत्रण से जुड़े चीनी आयातों पर लगने वाले कुछ टैरिफ को 10 फीसदी तक घटाएगा। साथ ही, धारा 301 के तहत दी गई टैरिफ छूटों को अगले साल 10 नवंबर तक बढ़ाएगा।

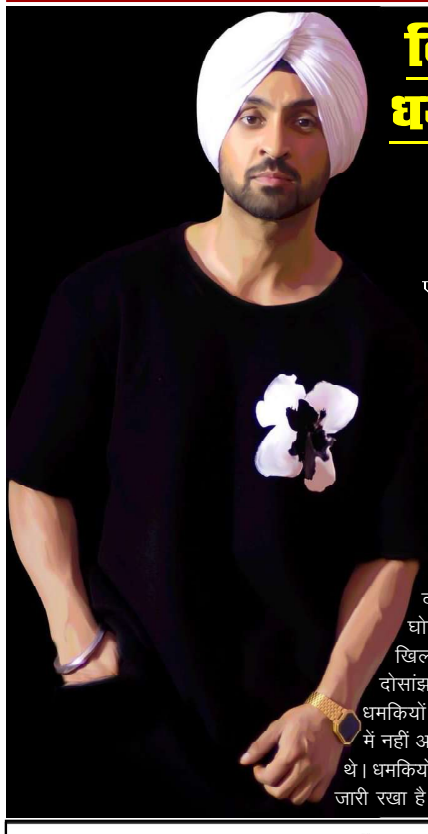

दिलजीत दोसांझ को फिर मिली धमकी, अमिताभ के पैर छूने से हैं नाराज; खालिस्तानी समर्थक ऑकलैंड में करेंगे ये काम

एजेंसी

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने श्औराश दूर पर हैं। उन्हें अमेरिकी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद नई धमकियां मिली हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक पर्थ में गायक के कॉन्सर्ट में कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में उनके अपकमिंग शो को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा बाधित करने की धमकी दी गई है। शांत हैं गायक अमिताभ बच्चन के पैर छूने के उनके कदम से उठे विवाद के बाद दोसांझ को प्रतिबंधित खालिस्तानी समूह एसएफजे से धमकियां मिल रही हैं। गायक ने इन धमकियों के बावजूद शांत बने रहने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संगीत कार्यक्रम की झलकियां साझा की हैं। अमिताभ के पैर छूने से शुरू हुआ विवाद विवाद तब शुरू हुआ जब कौन बनेगा करोड़पति 17 के एक प्रोमो में दिलजीत दोसांझ, अमिताभ बच्चन के पैर छूते हुए दिखाई दिए। इसके बाद, खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किए गए एक समूह, सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 29 अक्तूबर को गायक के खिलाफ धमकी जारी की। एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 1 नवंबर को होने वाले दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट को बंद कराने की भी चेतावनी दी थी। दिलजीत ने दी थी सफाई धमकियों के बाद दिलजीत ने स्पष्ट किया कि वह किसी फिल्म या गीत का प्रचार करने के लिए शो में नहीं आए थे, बल्कि पंजाब बाढ़ राहत प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के लिए आए थे। धमकियों के बावजूद जारी है दौरा दिलजीत दोसांझ ने धमकियों के बावजूद अपना अंतरराष्ट्रीय दौरा जारी रखा है और सीधे तौर पर उनसे बात करने से परहेज किया है।

त्योहारी मांग और जीएसटी सुधारों से बढ़ी कर्ज की रफ्तार, बैंकों की कमाई में तेजी के आसार

एजेंसी

नई दिल्ली। आने वाले महीनों में बैंकों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों की मुनाफे में बढ़त चार वजहों से हो सकती है, ज्यादा कर्ज देने की रफ्तार, जमा पर घटती ब्याज दरें, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी और असुरक्षित लोन (जैसे पर्सनल लोन) में फिसलन कम होना। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में लोन न चुकाने के मामलों में आई कमी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक इस समय जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरों को दोबारा तय कर रहे हैं, जिससे उनके खर्च कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) में लोन न चुकाने के मामलों में कमी आई है, जिससे बैंकों की हालत और बेहतर होगी। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ सकती है गिरावट रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) यानी ब्याज से होने वाली कमाई थोड़ा कम रह सकती है, लेकिन आगे जाकर ये स्थिर होने की उम्मीद है। कुछ बैंकों ने तो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन भी किया

है। ज्यादातर बैंकों के लिए लोन पर मिलने वाला ब्याज (यील्ड) थोड़ा घटा है, लेकिन इसका असर कम रहा क्योंकि बैंकों के लिए जमा और उधार पर ब्याज का खर्च भी घटा है। फिक्स डिपॉजिट में किए गए बदलावों का फायदा रिपोर्ट में कहा गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में किए गए बदलाव का पूरा फायदा बैंकों को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में दिखेगा। साथ ही, नकद आरक्षित अनुपात में कटौती का असर भी धीरे–धीरे नजर आएगा। बैंक प्रबंधन का अनुमान है कि तीसरी तिमाही में मुनाफे का मार्जिन स्थिर रहेगा और चौथी तिमाही से इसमें सुधार शुरू होगा, बशर्ते ब्याज दरों में आगे कोई कटौती न हो। जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन ने बढ़ाई कर्ज की मांग पहली तिमाही में जहां कर्ज की रफ्तार धीमी थी, वहीं दूसरी तिमाही में इसमें तेजी आई। इसका कारण है जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग। इसी वजह से सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 11.4 फीसदी तक पहुंच गई। क्या कहते हैं आकड़े? हालांकि दूसरी तिमाही में बैंकों के मुनाफे के कमजोर रहने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 3 अक्तूबर 2025 तक बैंकिंग सिस्टम के कुल कर्ज में तिमाही आधार पर 4.2% और सालाना आधार पर 11.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं जमा में तिमाही आधार पर 2.9% और सालाना आधार पर 9.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सार्वजनिक बैंकों में जमा की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी रही, लेकिन कुल मिलाकर जमा की रफ्तार अब भी कर्ज की तुलना में धीमी है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743